

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 42
21.06.2019 को उत्तर के लिए

वनों में आग

42. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
डॉ० सुभाष रामराव भामरे:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
डॉ० हिना गावीत:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) हाल के महीनों में देश के विभिन्न हिस्सों में वनों में आग लगने की रिपोर्ट की गई घटनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके कारण हुई मौतों/नष्ट हुई सार्वजनिक संपत्ति और वन-संपदा का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने देश में वनों में आग लगने की घटनाओं में खतरनाक तरीके से वृद्धि के संबंध में किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा कोई जांच कराई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं;
- (ग) क्या सरकार ने वनों की आग से प्रभावित राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने वनों में आग को रोकने के लिए स्थानीय सामुदायिक स्तर पर जागरूकता अभियान/प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए कोई प्रयास किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या सरकार का वनों में आग को नियंत्रित करने के लिए समुदायों और वन विभागों को प्रोत्साहित करने और बड़े पैमाने पर जन सामाजिक आंदोलन आरंभ करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) क्या सरकार का वनों में लगने वाली आग से मुकाबला करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली हेतु कोई तंत्र स्थापित करने और नई प्रौद्योगिकी तथा स्थानीय समुदायों को इसमें शामिल करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री प्रकाश जावडेकर)**

(क) महोदय, जब भी वनों में आग लगने की घटना होती है, भारतीय वन सर्वेक्षण दावानल का नियंत्रण करने के लिए विभिन्न राज्यों को अग्नि की चेतावनी जारी करता है। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जनवरी 2019 से 16 जून, 2019 तक सूचित की गई दावानल की घटनाओं का ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है। राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में 81.91 लाख रुपये तक की वन संपदा के नष्ट हो जाने और उत्तराखंड में 55.08 लाख रुपये तक की वन संपदा के नष्ट हो जाने की सूचना प्राप्त हुई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड द्वारा मानवीय क्षति की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। किसी अन्य राज्य से इस प्रकार की क्षति होने की कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) मंत्रालय ने विश्व बैंक के सहयोग से दावानल की स्थिति के विश्लेषण के संबंध में अध्ययन कराया है और 'भारत में दावानल प्रबंधन का सुदृढीकरण' अभिधीर्षक से एक अध्ययन रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दावानल निवारण, उसका पता लगाने, उसे नियंत्रित करने, आग लगने के पश्चात प्रबंधन, समुदायों के साथ समन्वय, अन्य अभिकरणों के साथ समन्वय आदि के संबंध में विभिन्न सिफारिशें शामिल हैं।

मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय दावानल संबंधी कार्य योजना जिसे अप्रैल 2018 में जारी किया गया था, को तैयार करने में अध्ययन से प्राप्त सूचना का उपयोग किया गया था।

(ग) जी हां। मंत्रालय ने वनों की आग से प्रभावित राज्यों/संघ शासित प्रदेश सरकारों को दावानल निवारण और प्रबंधन स्कीम से वित्तीय सहायता प्रदान की है। गत तीन वर्षों (31.3.2019 तक) के दौरान विभिन्न राज्यों को संवितरित की गई धनराशि का ब्यौरा अनुबंध-11 में दिया गया है।

(घ) दावानल निवारण और प्रबंधन स्कीम के तहत वित्तीय सहायता में जागरूकता अभियान/दावानल का निवारण करने में स्थानीय समुदाय के स्तर पर प्रतियोगिता करने के लिए कार्यक्रम शामिल हैं। राज्य वन विभाग दावानल निवारण के लिए जन जागरूकता और स्थानीय समुदायों को प्रशिक्षण प्रदान करने के कार्यक्रमलाप करता है।

(ड.) राज्य/संघ शासित प्रदेश के वन विभागों में दावानल का निवारण और नियंत्रण सहित विभिन्न वन सुरक्षा और संरक्षण उपायों में स्थानीय समुदाय, संयुक्त वन प्रबंधन समितियां (जेएफएमसी) और पारि-विकास समितियां (ईडीसी) आदि भी शामिल है।

(च) राष्ट्रीय दावानल कार्य योजना, दावानल आपदा में प्रभावी प्रतिक्रिया का प्रावधान करती है जिसके परिणाम-स्वरूप आग प्रभाव में कमी और त्वरित पुनःबहाली होती है क्योंकि देशभर में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा पहले से भेजी गई उपग्रह आधारित दावानल चेतावनियों की प्रणाली कार्यरत है। राष्ट्रीय दावानल कार्य योजना के अनुसार, दावानल का मुकाबला करने के लिए दावानल का जल्दी पता लगाने और त्वरित प्रतिक्रिया करने के लिए एक समर्पित फोन लाईन और वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के लिए वॉचटावर्स की स्थापना, ग्राउंड कू स्टेशन और फायर स्टेशन की अवस्थापना का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और सेना और पैरामिलिट्री शिविरों आदि को दावानल नियंत्रण हेतु त्वरित प्रतिक्रिया और वन स्टाफ और स्थानीय समुदायों की पहुंच के लिए सूचीबद्ध किया जाना है। अत्यधिक संवेदनशील दावानल आशंसित क्षेत्रों के समीप विभिन्न स्थानों पर दावानल का मुकाबला करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया हेतु अग्निशमन उपकरण भी प्रदान किए गए हैं।

अनुबंध I

वनों में आग के संबंध में श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, डॉ० सुभाष रामराव भामरे, श्री कुलदीप राय शर्मा और डॉ० हिना गावीत द्वारा दिनांक 21.06.2019 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारंकित प्रश्न सं. 42 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2019 के दौरान एमओडीआईएस सेंसर्स का उपयोग करते हुए एफएसआई द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सूचित की गई दावानल की चेतावनियों की संख्या (इसमें बड़ी, सतत और बार-बार लगने वाली दावानल) की संख्या शामिल है।

राज्य	दावानल चेतावनियां (1 जनवरी 2019 से 16 जून-2019)
अंडमान और निकोबार द्वीप	6
आंध्र प्रदेश	1731
अरुणाचल प्रदेश	848
असम	1893
बिहार	200
चंडीगढ़	0
छत्तीसगढ़	1581
दादरा और नागर हवेली	0
दमन और दीव	0
दिल्ली	2
गोवा	9
गुजरात	206
हरियाणा	14

हिमाचल प्रदेश	116
जम्मू और कश्मीर	35
झारखंड	354
कर्नाटक	1130
केरल	191
लक्षद्वीप	0
मध्य प्रदेश	2622
महाराष्ट्र	2302
मणिपुर	1729
मेघालय	1511
मिजोरम	2793
नागालैंड	1000
ओडिशा	1915
पुडुचेरी	0
पंजाब	33
राजस्थान	370
सिक्किम	9
तमिलनाडु	748
तेलंगाना	1181
त्रिपुरा	1194
उत्तर प्रदेश	784
उत्तराखंड	1502
पश्चिम बंगाल	243
कुल	28,252

अनुबंध-11

वनों में आग के संबंध में श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, डॉ० सुभाष रामराव भामरे, श्री कुलदीप राय शर्मा और डॉ० हिना गावीत द्वारा दिनांक 21.06.2019 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारंकित प्रश्न सं. 42 के भाग (ग और घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

(लाख में)

क्रम सं.	राज्य	2016-17 जारी	2017-18 जारी	2018-19 जारी
अन्य राज्य				
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	260.06
2	बिहार	88.59	75.00	57.17
3	छत्तीसगढ़	211.04	168.00	104.60
4	गुजरात	122.26	75.00	92.16
5	गोवा	0.00	0.00	87.83
6	हरियाणा	93.91	75.00	0.00
7	हिमाचल प्रदेश	331.36	276.70	0.00
8	जम्मू और कश्मीर	95.61	75.00	0.00
9	झारखंड	199.63	105.00	107.84
10	कर्नाटक	203.27	105.00	174.70
11	केरल	163.65	234.53	279.57
12	मध्य प्रदेश	281.15	168.00	628.25
13	महाराष्ट्र	372.58	321.58	787.28
14	ओडिशा	266.14	168.00	435.00
15	पंजाब	0.00	75.00	0.00
16	राजस्थान	174.22	105.00	98.82
17	तमिलनाडु	74.29	105.00	0.00

18	तेलंगाना	0.00	105.00	0.00
19	उत्तर प्रदेश	139.72	75.00	100.61
20	उत्तराखंड	304.03	168.00	438.38
21	पश्चिम बंगाल	92.83	75.00	54.14
	कुल	3214.28	2554.81	3706.41
पूर्वोत्तर और सिक्किम				
1	असम	0	0.00	93.23
2	अरुणाचल प्रदेश	181.34	102.00	89.08
3	मणिपुर	125.02	219.88	230.54
4	मेघालय	126.57	104.63	113.53
5	मिजोरम	131.29	90.59	110.47
6	नगालैंड	170.01	92.56	83.12
7	सिक्किम	119.73	148.59	0.00
8	त्रिपुरा	190.76	66.00	109.73
	कुल	1044.72	824.25	829.70
केंद्र शासित प्रदेश				
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	56.23	9.00	26.41
2	चंडीगढ़	74.52	8.00	1.00
3	दादर और नागर हवेली	0.00	0.00	0.00
4	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
5	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
6	नई दिल्ली	50.00	30.00	0.00
7	पांडिचेरी	0.00	30.00	49.84
	कुल	180.75	77.00	77.25
	कुल योग	4439.75	3456.06	4613.36
